

## विवरण

## विभिन्न उत्तरी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षित शिक्षकों की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण शिक्षकों की प्रतिशतता			
		उच्चतर माध्यमिक	उच्च स्कूल	मिडिल	प्राथमिक
1.	उत्तरी राज्य				
1.	हरियाणा	97	98	92	97
2.	हिमाचल प्रदेश	100	98	99	86
3.	जम्मू और कश्मीर	79	67	59	61
4.	पंजाब	99	99	97	99
5.	राजस्थान	98	97	97	98
6.	उत्तर प्रदेश	97	97	98	98
7.	चंडीगढ़	100	100	100	100
8.	दिल्ली	100	100	100	100
2.	पूर्वोत्तर राज्य				
1.	हिमाचल प्रदेश	67	53	43	46
2.	असम	30	30	36	68
3.	मणिपुर	46	32	29	50
4.	मेघालय	88	36	37	45
5.	मिजोरम	0	47	74	78
6.	नागालैंड	29	30	29	22
7.	सिक्किम	60	51	47	40
8.	त्रिपुरा	53	35	30	32

## बिहार में स्थित बिना भवन वाले प्राथमिक विद्यालय

577. श्री जनार्दन यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य के बांका, गोड़ा, देवघर और जमुई जिलों में ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय हैं जिनके अपने भवन नहीं हैं,

(ख) क्या सरकार उक्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण करने का विचार रखती है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) प्राथमिक स्कूलों के लिए भवन बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की हैं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय के परामर्श से इस विभाग द्वारा तैयार किए फार्मुले के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जवाहर रोजगार योजना के तहत प्राथमिक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 48% राशि उपलब्ध कराई जाती है यदि राज्य अपने हिस्से की 40% गैर-जवाहर रोजगार योजना तथा 12% जवाहर रोजगार योजना की राशि जुटाए

उपलब्ध सूचना के अनुसार आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत बिहार में निर्मित शिक्षण कक्षों की संख्या 18462 हैं। प्राथमिक स्कूल भवन की स्थिति के संबंध में जिलावार सूचना विभाग द्वारा नहीं रखी जाती।

#### Steps to Encourage Sports

578. SHRIMATI VEENA VERMA:  
SHRI AKHILESH DAS:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether in view of India's comparatively lower tally of medals won at the recent Asian Games, Government have taken any special steps to encourage sports in the country and to boost up the performance at international sports meets;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any comprehensive action plan is contemplated to give a boost to sports?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) Yes, Sir. The Government has undertaken a number of steps with a view to improve our performance in international sports events. They are as follows:

(i) National Sports Federations have been requested to draw up a detailed Long Term Development Plan (LTDP) incorporating requirement for promotion of sports. This is being reviewed closely. As per agreed programme all National Sports Federations will be given assistance for improving the standard of sports persons/teams.

(ii) The Federations have also been asked to hold National level tournaments for Sub-Juniors, Juniors and Seniors. The Federations are also given grants for equipment, foreign exposures and holding National and International tournaments. Foreign Coaches have also been provided to the National Sports Federations in selected disciplines to improve the

standards. The Sports Authority of India (SAI) holds regular coaching camps for selected teams and athletes.

(iii) A Scheme for assisting Promising Sports Persons and Supporting personnel has been recently formulated under which outstanding sports-persons can be given financial assistance upto Rs. 5.00 lakhs for getting themselves trained in India or abroad for improving their excellence in sports.

(iv) A National Sports Development Fund has also been set up with an initial contribution of Rs. 2.00 crores by the Government for the promotion and development of sports in country.

(v) To encourage sports persons, Government has also increased the prize money substantially for the medal winners in international sports events.

**उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश से कर्ण प्रयाग तक रेल-लाइन**

579. श्रीमती मालती शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के ऋषिकेश से कर्ण प्रयाग तक रेल-लाइन बिछाने का सर्वेक्षण किया गया था,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस सर्वेक्षण पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है, और

(घ) सर्वेक्षण रिपोर्ट को आधार पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

**रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) और (ख) एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। यह अभी भी प्रगति पर है और लगभग एक साल की अवधि में पूरा होने की संभावना है।

(ग) सर्वेक्षण की लागत 10 लाख रुपए और अभी तक 7 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।